माननीय न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता के समक्ष

रामो और अन्य-याचिकाकर्ता।

बनाम

कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण शहरी संपदा, फ़रीदाबाद और अन्य-प्रतिवादी।

1977 का नागरिक संशोधन संख्या 66।

28 नवंबर 1984.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का प्रथम) - धारा 9, 18 और 53 - सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - धारा 141 - भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिया गया पुरस्कार - मुआवजे में वृद्धि के लिए धारा 18 के तहत बनाया गया संदर्भ - दावेदार स्वयं अनुपस्थित उनके साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर - जिला न्यायाधीश ने योग्यता के आधार पर संदर्भ को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दिया गया मुआवजा उचित था - ऐसी प्रक्रिया - चाहे वैध हो - अदालत के पालन के लिए उचित पाठ्यक्रम - कहा गया।

माना गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में सीधे तौर पर उस स्थिति से निपटने का कोई प्रावधान नहीं है जहां संदर्भ का कोई पक्ष अनुपस्थित है, न ही ऐसा कोई प्रावधान है जो अदालत को गैर-अभियोजन के लिए संदर्भ को खारिज करने का आदेश पारित करने से रोकता है।. इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता के किसी भी प्रावधान की प्रयोज्यता पर अधिनियम में कोई रोक, व्यक्त या निहित नहीं है और सामान्य तौर पर संहिता के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 53 और धारा 141 के प्रावधानों द्वारा लागू किया जा रहा है। संहिता के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि डिफ़ॉल्ट रूप से संदर्भ को खारिज करने के आदेश को रद्द करने का आवेदन पोषणीय नहीं है। जहां दावेदार मामले में तय तारीख पर अनुपस्थित रहते हैं, तो अदालत के लिए उचित कदम यह है कि उपस्थिति में चूक के लिए संदर्भ को खारिज कर दिया जाए ताकि दावेदार सलाह दिए जाने पर संदर्भ की बहाली के लिए आवेदन कर सकें। न्यायालय के पास यह मानने का कोई अवसर नहीं है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि उचित थी।

(पैरा 5).

श्री आर जे लांबा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुड़गांव के न्यायालय के दिनांक 13 अक्टूबर 1976 के आदेश में संशोधन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सीपीसी की धारा 115 के तहत याचिका, जिसमें भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिए गए पुरस्कार की पुष्टि की गई थी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के धारा 18 के तहत संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील आर.एन. नरूला।

प्रतिवादी की ओर से वकील एम. पुरी।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता-

(1) यह पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव, दिनांक 13 अक्टूबर 1976 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिए गए पुरस्कार की पुष्टि की गई थी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ दिया गया था, (इसके बाद) अधिनियम कहा गया), अस्वीकार कर दिया गया।

2. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 14 जून, 1972 को याचिकाकर्ताओं की अधिग्रहित भूमि के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत पुरस्कार दिया। धारा 18 के तहत संदर्भ 20 जुलाई, 1972 को दिया गया था। पार्टियों की पहली उपस्थिति 9 जनवरी, 1976 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए। हालाँकि, 5 जून, 1976 को साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर मामले को साक्ष्य के लिए 11 अगस्त, 1976 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच, 17 जुलाई, 1976 को तारीख 11 अगस्त, 1976 से बदलकर 13 अक्टूबर, 1976 कर दी गई, क्योंकि पीठासीन अधिकारी को 11 अगस्त, 1976 को अदालत नहीं बुलानी थी। 17 जुलाई, 1976 के आदेश में यह कहा गया था , कि पार्टियों और वकील को तारीख में बदलाव के बारे में सूचित किया जाए। 13 अक्टूबर 1976 को दावेदारों-याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पाया कि अदालत के नोटिस पक्षों के विद्वान वकील को जारी करने का आदेश दिया गया था और उन्हें उक्त नोटिस की तामील कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री एस.बी. नागर को 10 अगस्त 1976 को अदालत का नोटिस दिया गया था और इसलिए, दावेदारों के पास सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन तय किए गए मुद्दों पर सबूत पेश करने के लिए कोई भी उनके लिए उपस्थित नहीं हुआ। उपस्थित न होने के संदर्भ को खारिज करने के बजाय, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मामले को आगे बढ़ाया और माना कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन की गई मुआवजा राशि उचित थी। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि 17 जुलाई 1976 को यह निर्देश दिया गया था कि पार्टियों और उनके वकील को नोटिस जारी किया जाए। माना कि पार्टियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। केवल उनके वकील को सूचित किया गया। दावेदारों के वकील ने उन्हें 11 अगस्त, 1976 से 13 अक्टूबर, 1976 तक की तारीख में बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया। किसी भी मामले में, विद्वान वकील ने तर्क दिया, यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था। अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ को उपस्थिति में चूक के कारण खारिज किया जा सकता है, लेकिन यह मानते हुए कि कलेक्टर का पुरस्कार उचित था, गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने ए. आभासभाई बनाम कलेक्टर, पंच मंडल (1) और पुल्गम्मा बनाम अतिरिक्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बैंगलोर, (2) पर भरोसा किया।

4. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क में दम नजर आया।

5. पुलम्मा के मामले (सुप्रा) में यह माना गया था कि अधिनियम में सीधे उस स्थिति से निपटने का कोई प्रावधान नहीं है जहां संदर्भ के लिए कोई पक्ष अनुपस्थित है, न ही ऐसा कोई प्रावधान है जो न्यायालय को बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से रोकता है। गैर-अभियोजन के लिए संदर्भ. इस प्रकार, अधिनियम में सिविल प्रक्रिया संहिता के किसी भी प्रावधान की प्रयोज्यता पर कोई रोक, व्यक्त या निहित नहीं है और सामान्य तौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों द्वारा लागू किया जा रहा है, और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 में यह नहीं कहा जा सकता कि डिफ़ॉल्ट रूप से संदर्भ को खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन पोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में, वर्तमान मामले में, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के लिए उचित कदम उपस्थिति में चूक के लिए संदर्भ को खारिज करना था ताकि दावेदार सलाह दिए जाने पर संदर्भ की बहाली के लिए आवेदन कर सकें। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि उचित थी।

6. इन परिस्थितियों में, पुनरीक्षण याचिका सफल होती है और अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और मामले को कानून के अनुसार संदर्भ के साथ आगे बढ़ने के लिए जिला न्यायाधीश, गुड़गांव को वापस भेज दिया गया है। पक्षों को 20 दिसंबर, 1984 को जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा